THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) The Central Govt. had convened a Conference of Sugar Ministers of all sugar producing States/UTs on 5.2.94. In that Conference, a Committee of Sugar Ministers of five State Govts. viz. Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka was constituted to recommend the Pricing Policy of Sugarcane. The Committee submitted its Report on 3.4.95. Another Conference of sugar Ministers of all the sugar producing States/UTs. was convened on 6.5.95 to conider the recommendations of that Committee. Though majority of the States/UTs. supported the formation of National Pricing Board for 'Sugarcane', there was difference of opinioin about its terms of reference. The Govt. decided to seek detailed views/suggestions from the State/UTs. in this regard. Views of Government of Maharashtra are awaited.

Autonomy to Development Commissioner for Iron and Steel

2455. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government are considering grant of greater autonomy in the liberalised regime to Development Commissioner for Iron and Steel to make it an effective development body;

(b) if so, the details of the changes under consideration/finalised and present status of the proposal; and

(c) the main functions presently assigned to DCIS and details of functions proposed to be assigned?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) The functions assigned to Development Commissioner for Iron and Steel (DCI&S) can be categorised as advisory, development and regulatory functions. The main functions are as follows:—

(a) Collection, processing and dissemination of basic information relating to the Iron and Steel industry and to act as the data bank of the Ministry of Steel.

(b) Monitoring of regional price and supply trends and suggesting to the Ministry remedial measures for correcting the imbalances, if any.

(c) Monitoring of import and export of iron and steel materials.

(d) Advice on matters relating to import and export policies of iron and steel.

(e) Management of distribution of iron and steel materials to the newly designated priority sectors such as Defence, Railways, State Small Industries Corporations, Engineering Goods Exporters and the North Eastern States.

(f) Allocation of materials to the State Small Scale Industries Corporations.

(g) Allocation of materials to remote areas like North Eastern States.

(h) Assistance to Engineering Goods Export Units through priority allocations and monitoring thereof.

(i) Survey of various segments of Steel Industry.

(j) Rendering assistance to the EAF units and the secondary sector, by way of capacity assessment, assistance in procurement of indigenous/imported raw material and import substitution measures aimed at overall develop development of the sector.

(k) Interface between the Government and different consumer groups to facilitate consumer-producer interaction.

(l) Co-ordination for movement of raw materials to Steel Plants.

(m) Vigilance functions to prevent misuse of steel obtained from regulared sources.

The functions assigned to DCI&S are reviewed by the Ministry of Steel from time to time in view of the changing role of this office in the liberalised scenario. The office of DCI&S is an attached office of the Ministry of Steel and there is no proposal at present to give it greater autonomy.

बीड़ी उद्योग के लिए नीतियां

2456. **श्रीमती आनन्दी जे० पटेल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी उद्योग और इसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्या नीतियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार बीड़ी का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय बीड़ी उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) बीड़ी विनिर्माण एक औद्योगिक कार्यकलाप है और इसे लघु उद्योग विकास संगठन की पंजीकृत योजना के तहत लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार की सभी पंजीकृत लघु उद्योग बीड़ी की इकाइयां उन सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रोत्साहनों, रियायतों तथा सुविधाओं के लिए पात्र हैं जो अन्य लघु उद्योग एककों के लिए उपलब्ध है।

श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि बीड़ी तथा सिगार प्रतिष्ठान में लगे कर्मचारियों के कल्याण के लिए तथा उनके कार्य की शर्तों को विनियमित करने और उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाये गये हैं:—

(1) बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1996

(2) बीड़ी कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

(3) बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1976

बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य दो अधिनियमों को केन्द्रीयकृत रूप से प्रबन्धित किया जा रहा है। बीड़ी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है **(नीचे देखिए)।**

(ख) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने सूचित किया है कि बीड़ी के आयात पर प्रतिबंध है तथा बीड़ी के आयात के लिए आयात लाइसेंस अनिवार्य है।

विवरण

बीड़ी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम
1.	स्थिर सह चल/स्थिर एलोपैथी तथा स्थिर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी।
2.	टी०बी० अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण हेतु योजना।
3.	टी०बी० से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के लिए घरेलू इलाज योजना।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के इलाज हेतु योजना।
5.	मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के इलाज हेतु योजना।
6.	कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों (घर खाता कर्मचारियों सहित) के इलाज के लिए योजना।
7.	चश्मे की खरीद के लिए बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8.	महिला बीड़ी कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ योजना।
9.	बीड़ी कर्मचारियों के बन्ध्यीकरण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु योजना।
10.	हृदय से संबंधित बीमारियों के संबंध में बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।